18 अप्रैल 2026
शनिवार

केशव टाइम्स

डिजिटल संस्करण

राजस्व वसूली में सुस्ती पर डीएम सख्त अनुपस्थित अधिकारियों से मांगा जवाब

2

एक नजर

बिहार सरकार का बड़ा एक्शन: दरभंगा में 128 राजस्व कर्मचारी सस्पेंड

दरभंगा । दरभंगा में डीएम कौशल कुमार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए जिले के विभिन्न अंचलों में तैनात 128 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर सामूहिक अवकाश लेकर विभागीय कार्यों में बाधा डालने का आरोप है। निलंबन 16 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा।

जिलाधिकारी ने निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र (प्रपत्र ह्यकह्न) गठित कर विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को सामूहिक अवकाश के रूप में अपनाकर सरकारी कार्यों में व्यवधान पैदा किया गया। निलंबित कर्मचारियों में सदर अंचल के 10, बहादुरपुर के 9, बहेड़ी के 12, हायाघाट के 8, हनुमाननगर के 5, सिंहवाड़ा के 10, केवटी के 11, जाले के 11, मनीगाछी के 7, तारडीह के 4, बेनीपुर के 9, अलीनगर के 4, बिरौल के 7, गौड़ाबौराम के 4, किरतपुर के 2, घनश्यामपुर के 5, कुशेश्वरस्थान के 5 और कुशेश्वरस्थान पूर्वी के 5 कर्मचारी शामिल हैं।

परिसीमन बिल राजनीतिक नोटबंदी, जल्दबाजी न करे सरकार' : शशि थरूर

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को लोक सभा में परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू करना देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। थरूर ने 2016 की नोट बंदी का हवाला देते हुए कहा कि, जिस तरह बिना पर्याप्त तैयारी के नोट बंदी लागू की गई थी, उसी तरह परिसीमन भी 'राजनीतिक नोट बंदी' साबित हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, ह्लआपने नोट बंदी भी अचानक लागू की थी और उसका नतीजा देश ने देखा। अब परिसीमन को भी उसी तरह आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसा न करें।ह्व उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि इस तरह के फैसलों से सहकारी संघवाद पर क्या असर पड़ेगा।

टायर फटने के बाद बस से टकराई कार, जिंदा जल गए पांच मासूम समेत 9 लोग

एजेंसी। बंगलूरू

कर्नाटक के यादगिरि जिले में शुक्रवार को मौत का एक ऐसा तांडव देखने को मिला, जिसने हर किसी का दिल दहला दिया है। दरअसल, सुरपुर तालुक के शांतापुरा क्रॉस के पास एक कार और निजी बस की आमने-सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार 10 लोगों में से नौ लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वालों में पांच मासूम बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली शुरूआती जानकारी के मुताबिक, हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कॉम्पैक्ट यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) का टायर अचानक फट गया। टायर फटते ही ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और कार डिवाइडर की दूसरी तरफ से आ रही निजी बस से जा टकराई। भिड़ंत होते ही कार आग का गोला बन गई।

रायचूर का रहने वाला था परिवार

पुलिस के अनुसार, कार सवार सभी लोग रायचूर जिले के सिरवार तालुक के रहने वाले थे। सभी लोग यादगिरि से अपने घर लौट रहे थे। वहीं, निजी बस बेंगलुरु से कलबुर्गी की ओर जा रही थी। गनीमत यह रही कि बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं और उन्हें समय रहते वाहन से बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है।

हादसे के वक्त कार में कुल 10 लोग सवार थे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे। जिला पुलिस अधीक्षक पृथ्वीक शंकर ने 9 मौतों की पुष्टि की है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस और कार, दोनों ही पूरी तरह जलकर खाक हो गए। अग्निशमन दल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी 20 यात्री सुरक्षित समय रहते बाहर निकलने में सफल रहे।

आसाराम आश्रम को झटका : अवैध कब्जे वाली जमीन पर अब सरकार करेगी कब्जा

एजेंसी। गांधीनगर

गुजरात हाई कोर्ट ने अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम ट्रस्ट को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़ी आश्रम की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब राज्य सरकार 45,000 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पर फिर से कब्जा कर सकेगी। मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे की बेंच ने यह आदेश सुनाया। बेंच ने सिंगल जज के उस पुराने फैसले को सही माना, जिसमें अहमदाबाद कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखा गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आश्रम ने बार-बार सरकारी शर्तों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अवैध कब्जे को वैध बनाने का कोई आधार नहीं बनता है। यह जमीन दशकों पहले केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए आश्रम को दी गई थी। उस समय लगभग 33,980 वर्ग मीटर जमीन आवंटित हुई थी। लेकिन सरकार ने कोर्ट को बताया कि आश्रम ने धीरे-धीरे करीब 50,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर लिया। सरकार ने जीपीएस और सैटेलाइट मैपिंग के जरिए सबूत पेश किए।

लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक खारिज हो गया

महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में 54 वोट से गिरा

■ **बिल को आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिला, पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े**

एजेंसी। नई दिल्ली

महिलाओं को विधानसभाओं और लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण देने और संसद की सीटें बढ़ाने संबंधी 131वां संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में खारिज हो गया। जिसके बाद अन्य दो बिलों को सरकार ने वापस ले लिए। बिल के पक्ष में 298 सदस्यों ने वोट किया, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया। कुल 528 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोट नहीं मिल सके, जिसके कारण बिल गिर गया। प्रस्तावित संशोधन के तहत 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा की सीटों को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्राविधान था। इसी तरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटें बढ़ाई जानी थीं, ताकि 2029 के चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। विपक्षी दलों के तीखे विरोध के बीच सरकार बिल को पास कराने में नाकाम रही।

महिला आरक्षण के नाम पर चुनावी नक्शा बदलने की शर्मनाक कोशिश: राहुल गांधी

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने परिसीमन प्रस्तावों का विरोध करते हुए भाजपा सरकार पर महिला आरक्षण की आड़ में देश के चुनावी नक्शे को बदलने की शर्मनाक कोशिश करने का आरोप लगाया।इसे राष्ट्र विरोधी काम बताते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे किसी कीमत पर नहीं होने देंगे और दक्षिण, पूर्वोत्तर तथा अन्य छोटे राज्यों के हितों की रक्षा करेंगे।महिला आरक्षण के लिए समर्थन दोहराते हुए राहुल गांधी ने सरकार को यह चुनौती भी दी कि वर्तमान 543 की संख्या पर ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तत्काल लागू करे और कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करेगी।

ओबीसी को नजरअंदाज करने का भी आरोप

लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने ओबीसी को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि इसके जरिए सरकार जाति जनगणना को दरकिनार कर ओबीसी भाई-बहनों को सत्ता में भागीदारी देने से बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि ओबीसी और दलितों को हिंदू कहते मगर उन्हें सत्ता की संरचना में कोई जगह नहीं देते और उनका असली एजेंडा "संविधान के ऊपर मनुवाद" है और सरकार यह पक्का करना चाहती है कि अगले 15 सालों तक जाति जनगणना का प्रतिनिधित्व पर कोई असर न पड़े।

हरिवंश तीसरी बार उपसभापति बने

एजेंसी। नई दिल्ली

राज्यसभा में शुक्रवार को एक ऐतिहासिक घटना दर्ज हुई। पहली बार किसी मनोनीत सांसद को उपसभापति पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह जिम्मेदारी हरिवंश नारायण सिंह को मिली है, जिन्हें हाल ही में द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिवंश को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में तीसरी बार चुने जाने पर बधाई दी। बधाई संदेश में जेपी से लेकर चंद्रशेखर तक का जिक्र पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल जैसे निर्णयों का मुखर विरोध करने वाले बिहार के जननेता के तौर पर लोकप्रिय रहे जयप्रकाश नारायण (जेपी) का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ है। उन्होंने

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का भी जिक्र किया। बतौर लेखकर हरिवंश के जीवन का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज उनकी जयंती के दिन तीसरे कार्यकाल के निर्विरोध चुना जाना इस अवसर को खास बनाता है। पीएम ने कहा कि पूरे सदन को आप पर गहरा विश्वास है, हरिवंश जी की कार्यशैली का सभी सम्मान करते हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हरिवंश जी के लेखों में धार है और उनका काम सराहनीय है। हरिवंश जी सभी की बातें सुनते हैं और उनका यह नया कार्यकाल समर्पण और संतुलन से आगे बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष के खाली पद को लेकर केंद्र खरगे ने को घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने हरिवंश को बधाई देते हुए कहा कि हमें इस बात से तकलीफ है संवैधानिक अनुच्छेद 93 में निहीत संवैधानिक भावना के विपरित लोकसभा में 2019 से उपाध्यक्ष का पद खाली है। सात वर्षों से वह रिक्त है, कितना अच्छा होता कि राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी ऐसी ही हुआ होता। आप प्रजातंत्र की बात करते हैं और सात साल से एक उपाध्यक्ष को चुन नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हर कोई लोकतंत्र की बात करता है।

कर्नाटक : कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी समेत 16 लोगों को उम्रकैद

एजेंसी। बंगलूरू

कर्नाटक के भाजपा नेता योगेश गौड़ा हत्याकांड में सजा की अवधि (क्वांटम ऑफ सेंटेंस) को लेकर बंगलूरू की एमएलए/एमपी विशेष अदालत ने विनय कुलकर्णी समेत 16 दोषियों को हत्या और साजिश के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने उन पर 30,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया। बेंगलुरु की जन प्रतिनिधि सभा की विशेष अदालत ने शुक्रवार को भाजपा नेता योगेश गौड़ा की हत्या के मामले में दोषी पाए गए कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी और अन्य आरोपियों को सजा सुनाई।विनय कुलकर्णी पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं। अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया था। अदालत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और दोषी कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के वकीलों की अंतिम दलीलें पूरी हो गईं। इसके बाद न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने मामले को स्थगित करते हुए फैसला सुनाने के लिए शुक्रवार की तारीख तय की थी। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में भावुक माहौल देखने को मिला। दोषियों के परिजन बड़ी संख्या में मौजूद थे और कई लोग रोते हुए नजर आए।

केशव टाइम्स
डिजिटल संस्करण

बक्सर, 18 अप्रैल 2026
website:keshavtimes.com
e-mail:keshavtimes1@gmail.com

21 अप्रैल को बक्सर में रोजगार शिविर, 400 पदों पर होगी भर्ती

- **दो निजी कंपनियां करेंगी मौके पर चयन, 10वीं से स्नातक व आईटीआई पास अभ्यर्थियों को मिलेगा अवसर**

केटी न्यूज/बक्सर

जिला नियोजनालय बक्सर की ओर से आगामी 21 अप्रैल को रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह शिविर संयुक्त श्रम भवन, आईटीआई फील्ड स्थित जिला नियोजनालय परिसर में आयोजित होगा। शिविर का संचालन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया जाएगा। इसमें दो निजी कंपनियां भाग लेंगी और योग्य अभ्यर्थियों का मौके पर ही चयन करेंगी। पहली कंपनी लेंसकार्ट है, जिसमें ऑपरेटर पद के लिए 200 रिक्तियां हैं। चयनित अभ्यर्थियों को 12 हजार 726 रुपये से 15 हजार 210 रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण रखी गई है। कार्यस्थल भिवाड़ी, राजस्थान होगा। पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कंपनी की ओर से उपस्थिति प्रोत्साहन राशि, रियायती भोजनालय तथा बस सेवा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी कंपनी आइडेमिया सिसकॉम है, जिसमें एटीएम कार्ड एवं सिम कार्ड निर्माण कार्य के लिए मशीन ऑपरेटर पद पर 200 नियुक्तियां की जाएंगी। चयनित अभ्यर्थियों को 11 हजार 500 रुपये से 14 हजार 500 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा। आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक, आईटीआई एवं डिप्लोमा रखी गई है। कार्यस्थल नोएडा होगा। कंपनी की ओर से 900 रुपये प्रोत्साहन राशि, निःशुल्क दोपहर व रात्रि भोजन तथा अतिरिक्त कार्य के लिए दोगुना भुगतान दिया जाएगा। प्रभारी जिला नियोजन पदाधिकारी ने बताया कि रोजगार शिविर में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य है। जो युवक-युवतियां अब तक निबंधन नहीं करा सके हैं, वे राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि शिविर में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इच्छुक अभ्यर्थी अपने जीवनवृत्त, आधार कार्ड तथा आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित हो सकते हैं। नियुक्ति की सभी शर्तों के लिए संबंधित नियोजक स्वयं जिम्मेदार होंगे, जबकि नियोजनालय की भूमिका केवल सुविधा प्रदाता की रहेगी।

जिला नियोजन पदाधिकारी ने जिले के बेरोजगार युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रोजगार के इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

शिक्षा अधिकारी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, दोनों पालियों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित

बक्सर। शुक्रवार को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित शिक्षा अधिकारी की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त माहौल में संपन्न हो गई। जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसके कारण सभी केंद्रों पर परीक्षा सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हुई। जिला नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम पाली में सामान्य भाषा विषय की परीक्षा आयोजित की गई। इस पाली में कुल 9060 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिसमें 3543 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 5517 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। राहत की बात यह रही कि किसी भी परीक्षा केंद्र से निष्कासन की सूचना प्राप्त नहीं हुई। वहीं द्वितीय पाली में सामान्य अध्ययन विषय की परीक्षा संपन्न हुई। इसमें भी कुल 9060 परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई थी, जिनमें 3528 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। दूसरी पाली में 5532 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस पाली में भी किसी अभ्यर्थी को निष्कासित नहीं किया गया। जिला नियंत्रण कक्ष के अनुसार जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी तथा केंद्रों के अंदर कड़ी निगरानी रखी गई। अधिकारियों द्वारा लगातार विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया गया।

राजस्व वसूली में सुस्ती पर डीएम सख्त अनुपस्थित अधिकारियों से मांगा जवाब

- **बैठक में परिवहन, दाखिल-खारिज, बसेरा-2 और लंबित आवेदनों पर फटकार एक सप्ताह में सुधार का अल्टीमेटम**

केटी न्यूज/बक्सर

जिलाधिकारी साहिला की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभाकक्ष में राजस्व, आंतरिक संसाधन एवं परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति, राजस्व वसूली, लंबित मामलों के निष्पादन तथा सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। कई विभागों की धीमी कार्यशैली पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया।

आंतरिक संसाधन समीक्षा के दौरान वनों के क्षेत्र पदाधिकारी बक्सर, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बक्सर तथा राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश दिया।

राजस्व वसूली की समीक्षा में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने के बाद भी सोन नहर प्रमंडल बक्सर की वसूली मात्र 75.12 प्रतिशत और सोन नहर प्रमंडल आरा की वसूली 66.58 प्रतिशत ही रही। डीएम ने निर्देश दिया कि जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ठोस कार्ययोजना बनाएं और वसूली अभियान तेज करें।

जिला परिवहन पदाधिकारी को एमवीआई और ईएसआई कार्यों की नियमित समीक्षा कर राजस्व बढ़ाने का निर्देश दिया गया। साथ ही रोको-टोको अभियान के तहत हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों की सघन जांच कर जुमार्ना वसूली सुनिश्चित करने को कहा गया। शहर में वेडिंग जोन और पार्किंग जोन चिन्हित करने तथा गलत पार्किंग करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई का आदेश भी दिया गया।

अभियान बसेरा-2 की समीक्षा में भूमिहीन लाभुकों को शीघ्र पर्चा देने पर जोर दिया गया। सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पंचायत स्तर पर चल रहे कल्याण विभाग के कैंपों में विकास मित्रों के माध्यम से भूमिहीन परिवारों की पहचान कर आवेदन लिए जाएं।

परिमार्जन प्लस के तहत 75 और 120 दिनों से लंबित आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर और डुमरांव को बसेरा-2 व परिमार्जन प्लस के आवेदनों की पाक्षिक समीक्षा करने को कहा गया।

दाखिल-खारिज मामलों में 75 व 120 दिनों से लंबित आवेदनों को शून्य करने का लक्ष्य तय किया गया। वहीं मापी से जुड़े सभी लंबित मामलों को भी एक सप्ताह के भीतर निपटाने का आदेश दिया गया।

डीएम ने सभी अंचलाधिकारियों को कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने और योजनाओं की दैनिक समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद भी राजस्व वसूली संतोषजनक नहीं है, इसलिए आमजनों को जागरूक कर वसूली में तेजी लाई जाए।

तेज गर्मी की आशंका को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर माइकिंग के माध्यम से लोगों को सतर्क करने का निर्देश भी दिया गया।

सरकारी भूमि के दाखिल-खारिज, लैंड बैंक के लिए 5 एकड़ से अधिक एवं कम भूमि की पहचान, एमजेसी-सीडब्लूजेसी मामलों में समय पर शपथपत्र दाखिल करने तथा नीलाम पत्र वादों में बड़े बकायेदारों से राशि वसूली के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश भी जिलाधिकारी ने दिया।

बैठक के अंत में डीएम ने स्पष्ट कहा कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी और तय समय सीमा में परिणाम दिखना चाहिए।

निमेज पंचायत में पोषण पखवाड़ा के तहत जागरूकता सत्र आयोजित

केटी न्यूज/ब्रह्मपुर

प्रखंड क्षेत्र की निमेज पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 19 पर पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत शुक्रवार को जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समुदाय को संतुलित आहार, पूरक पोषण तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर पिरामल फाउंडेशन के गांधी फेलो प्रदीप ने उपस्थित महिलाओं एवं ग्रामीणों को पूरक पोषण के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा छोटे बच्चों के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर उचित पोषण मिलने से मां और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर रहता है तथा कुपोषण जैसी समस्याओं से बचाव संभव है। उन्होंने सरल भाषा में बताया कि दैनिक भोजन में हरी सब्जियां, दाल, दूध, फल, अंडा, अनाज एवं अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। साथ ही साफ-सफाई, समय पर टीकाकरण तथा नियमित स्वास्थ्य जांच की भी आवश्यकता बताई।कार्यक्रम में समुदाय की गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की सक्रिय भागीदारी रही। सभी प्रतिभागियों ने पोषण संबंधी जानकारियों को गंभीरता से सुना और अपने परिवार में स्वस्थ खानपान अपनाने का संकल्प लिया। आयोजकों ने बताया कि पोषण पखवाड़ा अभियान के माध्यम से गांव-गांव में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सके। ऐसे कार्यक्रमों से समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक संदेश पहुंच रहा है।

स्थानीय लोगों ने इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की पहल बेहद जरूरी है, जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके और स्वस्थ समाज का निर्माण हो।

डुमरांव में भाकपा-माले का प्रतिनिधि चुनाव संपन्न, 15 सदस्य जाएंगे राज्य सम्मेलन

- **27 प्रत्याशियों ने ठोकी दावेदारी, सुबह से शाम तक चला मतदान, दरभंगा सम्मेलन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह**

केटी न्यूज/डुमरांव

भाकपा-माले के आगामी 12वें बिहार राज्य सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों के चयन को लेकर गुरुवार को डुमरांव स्थित जिला कार्यालय में मतदान कराया गया। शांतिपूर्ण माहौल में हुए इस चुनाव में 27 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 15 प्रतिनिधियों का चयन किया गया। चयनित प्रतिनिधि आगामी 16 से 18 मई तक दरभंगा जिले के लहेरियासराय में आयोजित राज्य सम्मेलन में बक्सर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 4 बजे तक चली। पूरे दिन पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकताओं की आवाजाही बनी रही। मतदान को पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए भोजपुर जिले के वरिष्ठ नेता एवं पार्टी राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड संजय सिंह पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे।

चुनाव में पार्टी के पूर्व जिला सचिव मनोहर, वर्तमान जिला सचिव नवीन कुमार, पूर्व विधायक सह आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड अजीत कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा विभिन्न पंचायतों और प्रखंडों से जुड़े निर्वाचक मंडल के सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया।

निर्वाचक मंडल में मणियां के मुखिया, बसांव कला के मुखिया, बीडीसी सदस्य, सरपंच, पूर्व वार्ड पार्षद बुधिया देवी सहित जिला, प्रखंड और पंचायत कमेटी के सदस्य शामिल रहे। सभी मतदाताओं ने बारी-बारी से मतदान कर संगठनात्मक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई।

जिला सचिव कॉमरेड नवीन कुमार ने कहा कि भाकपा-माले में संगठनात्मक चुनाव पूरी तरह लोकतांत्रिक और संतुलित व्यवस्था के तहत कराए जाते हैं। सम्मेलनों में पिछले कार्यकाल की समीक्षा की जाती है और आगामी दिनों के संघर्षों की रणनीति तय होती है।

उन्होंने कहा कि राज्य सम्मेलन में बिहार में बढ़ती दमनकारी नीतियों, जनसरोकारों के मुद्दों, नए क्षेत्रों में संगठन विस्तार तथा लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ संयुक्त मोर्चा की रणनीति पर विचार-विमर्श होगा। सम्मेलन के अंतिम चरण में नई राज्य कमेटी का गठन कर नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

बक्सर में गैस आपूर्ति पर प्रशासन सख्त कालाबाजारी रोकने को लगातार छापेमारी

केटी न्यूज/बक्सर

जिले में रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा जमाखोरी-कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि बक्सर जिले में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों की कुल 27 गैस एजेंसियां कार्यरत हैं। इनमें इंडियन ऑयल की 13, भारत पेट्रोलियम की 6 तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम की 8 एजेंसियां शामिल हैं। जिले में घरेलू गैस उपभोक्ताओं की संख्या 3 लाख 50 हजार से अधिक है। कंपनीवार आंकड़ों के अनुसार इंडियन ऑयल के 2,02,360, भारत पेट्रोलियम के 57,517 तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 90,668 उपभोक्ता हैं। 13 मार्च से 16 अप्रैल 2026 तक कुल 1,61,616 गैस सिलेंडरों का वितरण किया जा चुका है, जबकि 16 अप्रैल तक एजेंसियों के पास 2,432 सिलेंडर शेष थे। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार जिले में प्रतिदिन औसतन 6,419 सिलेंडरों की मांग है, जबकि प्रतिदिन 5,595 रीफिल की आपूर्ति हो रही है। फिलहाल 26,549 बुकिंग लंबित हैं और लगभग 4.7 दिन का बैकलॉग है। गैस वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए शहरी उपभोक्ताओं को अंतिम डिलीवरी के 25 दिन बाद तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को 45 दिन बाद नई बुकिंग की अनुमति दी गई है। निर्धारित अंतराल पर घर-घर पहुंच सेवा के माध्यम से ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सभी एजेंसियों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलास्तरीय अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी लगातार एजेंसियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर रहे हैं। अब तक कालाबाजारी के दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 16 अप्रैल को ही 38 गैस एजेंसियों और अन्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। गैस आपूर्ति संबंधी शिकायतों के लिए दूरभाष संख्या 06183-223333 जारी की गई है। अब तक कुल 1055 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 1003 का त्वरित निपटारा कर दिया गया है। शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है।

पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जयंती पर द एमिटी स्कूल ने 12 टॉपर्स व 6 अनाथ छात्रों की फीस की माफ

केटी न्यूज/नावानगर

सोनवर्षा के द एमिटी स्कूल में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जयंती के अवसर पर सराहनीय पहल करते हुए 12 मेधावी टॉपर छात्रों एवं 6 अनाथ छात्रों की स्कूल फीस माफ करने की घोषणा की है। यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सत्र 2025-26 में एलकेजी से कक्षा 10वीं तक के 12 टॉपर छात्रों को सत्र 2026-27 के लिए 50 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक फीस में छूट दी गई है। वहीं चयनित 6 अनाथ छात्रों को पूरी तरह निशुल्क शिक्षा देने का निर्णय लिया गया है। विद्यालय के डायरेक्टर अमरेंद्र राजेश ने बताया कि यह योजना “नीजु सिंह फ्री एजुकेशन स्कीम फॉर टॉपर्स” एवं “हरेंद्र सिंह व शांति सिंह फ्री एजुकेशन स्कीम फॉर ऑर्फन” के तहत चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली एवं जरूरतमंद बच्चों को आगे बढ़ाना विद्यालय की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी शिक्षा और समाजसेवा के प्रतीक थे। उनकी जयंती पर इस तरह की पहल कर विद्यालय परिवार ने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। विद्यालय लगातार शिक्षा के साथ सामाजिक सरोकारों को भी प्राथमिकता देता रहा है। विद्यालय के अनुसार टॉपर छात्रों में विभिन्न कक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों का चयन वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर किया गया है। इन छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं अनाथ छात्रों के चयन में पारदर्शिता बरती गई है ताकि जरूरतमंद बच्चों को लाभ मिल सके। इस अवसर पर विद्यालय के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, शिक्षकगण एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहे। विद्यालय की इस पहल की क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सख्ती, अवैध क्लीनिकों पर होगी कार्रवाई

- **जैव चिकित्सा कचरे का खुले में निस्तारण करने वालों पर गिरेगी गाज, सभी नगर निकायों को भेजी जाएगी सूची**

केटी न्यूज/बक्सर

समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त निहारिका छवि की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित निजी क्लीनिकों, नर्सिंग होमों तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थानों की कार्यप्रणाली, पंजीकरण स्थिति और जैव चिकित्सा कचरे के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान कई मामलों में लापरवाही सामने आने पर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। उप विकास आयुक्त ने सिविल सर्जन बक्सर को निर्देशित किया कि जिले में संचालित ऐसे गैर-सरकारी क्लीनिकों की तत्काल पहचान की जाए, जो समय पर जैव चिकित्सा कचरे का निष्पादन नहीं कर रहे हैं या सार्वजनिक स्थलों पर फेंककर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में जैव चिकित्सा कचरा उठाव से जुड़ी एजेंसी संगम मेडिसर्व के प्रतिनिधि को भी तलब किया गया। उप विकास आयुक्त ने एजेंसी प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि बकाया राशि से संबंधित विपत्र शीघ्र सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव के समक्ष समर्पित करें, ताकि लंबित भुगतान प्रक्रिया का निपटारा किया जा सके और सेवा कार्य प्रभावित न हो।

समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि जिले में कई निजी क्लीनिक बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। इस पर उप विकास आयुक्त ने सिविल सर्जन को कड़ी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिया कि अवैध रूप से चल रहे निजी क्लीनिकों की जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे संस्थानों में जैव चिकित्सा कचरे का सुरक्षित निस्तारण हो रहा है या नहीं।

उन्होंने कहा कि केवल पंजीकरण होना पर्याप्त नहीं है। ऐसे निजी स्वास्थ्य संस्थान जो पंजीकृत तो हैं, लेकिन निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सिविल सर्जन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति बक्सर को संयुक्त रूप से निर्देश दिया गया कि सभी पंजीकृत निजी संस्थानों की विधिवत जांच कराई जाए। जहां भी मानकों की अनदेखी या जैव चिकित्सा कचरा प्रबंधन में गड़बड़ी मिले, वहां नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि जिन निजी संस्थानों ने कचरा उठाव एजेंसी से अनुबंध नहीं किया है और स्वयं कचरे का अनुचित तरीके से निस्तारण कर रहे हैं, उनकी सूची तैयार कर प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए। ऐसे संस्थानों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।

उप विकास आयुक्त ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निर्देश दिया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची जिले के सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को यथाशीघ्र भेजी जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर भी निगरानी बढ़ाई जा सके और नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जा सके।

बैठक में अधिकारियों ने माना कि जैव चिकित्सा कचरे का गलत निस्तारण गंभीर जनस्वास्थ्य संकट पैदा कर सकता है। इससे संक्रमण फैलने, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने तथा आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका रहती है। इसी कारण प्रशासन अब इस मुद्दे पर पूरी सख्ती के मूड में दिख रहा है।

बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में सभी निजी एवं सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को नियमों के दायरे में रहकर काम करना होगा, अन्यथा कार्रवाई तय है।

एक नजर

चौसा में गुप्त सूचना पर पुलिस की कार्रवाई, हथियार के साथ तीन युवक गिरफ्तार

चौसा। चौसा क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों के पास से एक देशी पिस्तौल तथा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी इलाके में कुछ युवक संदिग्ध परिस्थितियों में एकत्र होकर किसी योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने देर रात छापेमारी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से एक देशी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने गिरफ्तार युवकों की पहचान मुसफिरगंज निवासी अंकित कुमार उर्फ अंकित वर्मा, मित्रलोक कॉलोनी निवासी अभिषेक कुमार ठाकुर उर्फ भोलू तथा सन्नी कुमार सिंह के रूप में की है। गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपितों को थाना लाकर पूछताछ की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि बरामद हथियार और कारतूस को जब्त कर लिया गया है तथा आरोपितों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई है। सभी आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आरोपित किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे या किसी अन्य उद्देश्य से वहां जुटे थे। इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है।

शादी के दो साल में उजड़ गई जिंदगी: बुलेट और चेन की मांग ने ली विवाहिता की जान, सास गिरफ्तार

कृष्णाब्रह्म। दहेज की लालच ने एक और बेटी की जिंदगी निगल ली। कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के रमसर मठिया गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। मायके पक्ष ने आरोप लगाया है कि बुलेट बाइक और सोने की चेन की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने उसे जहर देकर मार डाला। घटना के बाद गांव में मातम पसरा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति फरार बताया जा रहा है।मृतका के भाई बब्लू गिरी के बयान पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उसकी बहन की शादी 28 मई 2023 को रमसर मठिया गांव निवासी अंग्रहीत गिरी के पुत्र पवन गिरी से हुई थी। शादी में परिजनों ने अपनी क्षमता के अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन विवाह के पहले से ही ससुराल पक्ष बुलेट बाइक और सोने की चेन की मांग पर अड़ा था। समाज के लोगों के हस्तक्षेप के बाद शादी तो हो गई, लेकिन विवाहिता की मुसीबतें वहीं से शुरू हो गईं। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही विवाहिता को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। सास उसे ताना देती थी कि “कंगाल घर की लड़की” लाई गई है। दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सिलसिला लगातार चलता रहा। विवाहिता सब कुछ सहकर अपना घर बसाने की कोशिश करती रही, लेकिन लालच कम नहीं हुआ।आरोप है कि 15 अप्रैल की रात पति पवन गिरी और उसकी मां ने मिलकर विवाहिता को जहर दे दिया। हालत बिगड़ने पर आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष में कोहराम मच गया। माता-पिता और भाई-बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है।सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के भाई के बयान पर पति और सास के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी सास को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार पति की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है।जिस घर से बेटी डोली में विदा हुई थी, वहां दो साल बाद उसकी अर्थी उठी। घटना ने समाज के सामने फिर सवाल खड़ा कर दिया है–आखिर दहेज की यह आग कब बुझेगी।

लंबित कांडों पर सख्ती : डुमरांव अंचल के दो थानों में औचक जांच, लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी

केटी न्यूज/डुमरांव

डुमरांव अनुमंडल क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को चुस्त करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए अंचल निरीक्षक अरविंद कुमार ने वासुदेवा और मुरार थाना का औचक निरीक्षण किया। अचानक हुए इस निरीक्षण से दोनों थानों में हलचल मच गई। निरीक्षक ने लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए साफ शब्दों में कहा कि अब मामलों को दबाकर रखने या जांच में ढिलाई की गुंजाइश नहीं है।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने केस डायरी, अनुसंधान की वर्तमान स्थिति, वारंट निष्पादन, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और पेंडिंग मामलों की फाइलों की बारीकी से जांच की। कई मामलों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई तेज करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है और इसमें किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीआई अरविंद कुमार ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि हत्या, लूट, महिला उत्पीड़न, भूमि विवाद और अन्य गंभीर मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। साथ ही वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान चलाकर तेज करने तथा फरार अपराधियों पर लगातार दबाव बनाए रखने को कहा गया।

उन्होंने थाना स्तर पर नियमित केस मॉनिटरिंग, शिकायतों के त्वरित निष्पादन और आम लोगों से बेहतर संवाद कायम रखने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के रख-रखाव, मालखाना व्यवस्था और पुलिसकर्मियों की कार्यशैली का भी जायजा लिया गया।

अंचल निरीक्षक ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता या जांच में अनावश्यक देरी पाई गई तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय मानी जाएगी। अचानक हुए इस निरीक्षण को क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और सक्रिय बनाने की दिशा में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

चौसा में अंबेडकर जयंती पर सांस्कृतिक समागम, दुगोला चैता में उमड़ी भारी भीड़

- **बाबा साहब के विचारों और शिक्षा के संदेश के साथ देर रात तक गूंजता रहा लोकगीतों का सुर**

केटी न्यूज/चौसा

नगर पंचायत चौसा स्थित आदर्श उच्च विद्यालय के खेल मैदान में गुरुवार की रात भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुगोला चैता कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और देर रात तक लोक संगीत का आनंद लेते रहे। आयोजन स्थल पर उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला।

कार्यक्रम का आयोजन बक्सर थर्मल पावर मजदूर यूनियन के महामंत्री एवं पूर्व जिला पार्षद अधिवक्ता डॉ. मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया। समारोह का उद्घाटन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रो. आर.के. पांडेय तथा स्थानीय ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के बाद अतिथियों का पारंपरिक तरीके से पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया गया।

सांस्कृतिक संध्या में उत्तर प्रदेश के बलिया से आए लोक कलाकार कमलेश देहाती और छपरा की चर्चित गायिका मनीषा राज ने चैता गायन की शानदार प्रस्तुति दी। लोकगीतों की मधुर धुन पर दर्शक झूम उठे। कलाकारों की प्रस्तुति ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। देर रात तक तालियों और उत्साह का सिलसिला जारी रहा।

इस मौके पर डॉ. मनोज कुमार यादव ने कहा कि बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने समाज के हर वर्ग को शिक्षा का अधिकार दिलाने का कार्य किया। उनके बताए रास्ते पर चलकर समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक और आर्थिक उन्नति का सबसे बड़ा साधन है, इसलिए हर परिवार को अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

प्रो. आर.के. पांडेय ने कहा कि डॉ. अंबेडकर के विचार आज भी समाज को दिशा देने वाले हैं। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम बताते हुए युवाओं से जागरूक बनने की अपील की।

कार्यक्रम में कुशवाहा महासभा के अध्यक्ष रामाशीष कुशवाहा, प्रो. रमेश चंद्र श्रीवास्तव, विनोद कुमार सिंह, संजय सिंह, अधिवक्ता राम लखन पाल, सुनील कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजन की सफलता को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रसन्नता जताई।

कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में डीडीसी सख्त, छात्रावासों में शीघ्र नामांकन व लंबित योजनाएं पूरी करने का निर्देश

- **रिक्त सीटों को भरने, विद्यालयों में शिक्षक प्रतिनियुक्ति और भवन मरम्मत कार्य में तेजी लाने पर जोर**

केटी न्यूज/बक्सर

समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उप विकास आयुक्त निहारिका छवि की अध्यक्षता में जिला कल्याण कार्यालय, जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न छात्रावासों, विद्यालयों तथा निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी बक्सर, छात्रावास प्रबंधक डॉ. अंबेडकर कल्याण छात्रावास 11 नंबर लख, डॉ. अंबेडकर कल्याण बालिका छात्रावास कोईरपुरवा, विद्यालय प्रबंधक पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास, छात्रावास समन्वयक जननायक कपूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, भवन निर्माण विभाग, भवन निर्माण निगम लिमिटेड सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने डॉ. अंबेडकर कल्याण बालिका एवं बालक छात्रावासों में रिक्त सीटों पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि रिक्त सीटों के विरुद्ध जल्द से जल्द नामांकन प्रक्रिया पूरी कर योग्य विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जाए। डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय, रामपुर बक्सर की समीक्षा के क्रम में भवन निर्माण निगम लिमिटेड के कार्यपालक अभियंता को विद्यालय परिसर में चल रहे मेंटेनेंस कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। डीडीसी ने कहा कि छात्र-छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना जरूरी है।

बैठक में सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस दौरान पाया गया कि कई योजनाएं अब भी लंबित हैं। इस पर उप विकास आयुक्त ने स्थानीय क्षेत्र संगठन कार्य प्रमंडल, बक्सर के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि सभी लंबित योजनाओं का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराया जाए।

समीक्षा के दौरान अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी डुमरांव ने नव निर्मित विद्यालय भवन में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति को अत्यंत आवश्यक बताया। इस पर उप विकास आयुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी बक्सर को निर्देशित किया कि नव निर्मित विद्यालय में जल्द से जल्द शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

उप विकास आयुक्त ने कहा कि कल्याण विभाग की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सभी विभागीय पदाधिकारी समन्वय बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्य करें तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें।

आज से शुरू होगा गरमा मूंग और मक्का बीज का वितरण, इंतजार की घड़िया समाप्त

रबी फसल गेहूं के कटनी के बाद मूंग व मक्का बीज की शुरू होती है बुआई

केटी न्यूज/डुमरांव

सरकार की तरफ से गरमा बीज मूंग और मक्का का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रबी फसल की कटनी हो जाने के बाद उनका खेत परती हो गया था। गरमा हाइब्रिड बीज मक्का और मूंग की रोपनी को लेकर बीज का इंतजार किसान कर रहे थे। किसान प्रतिदिन बीएओ कार्यालय पहुंच बीज आने का इंतजार कर रहे थे। किसान समन्वयक और सलाहकारों के द्वारा किसानों को जैसे ही यह बताया गया कि मूंग और मक्का बीज का प्रखंड कृषी कार्यालय में पहुंच गया है, जिसका वितरण शनिवार को किया जाएगा। इतनी बात सुनते ही किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई, और घर लौट बीज लेने के फिराक में जुट गए। उन्हें बताया गया की पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर बीज का वितरण किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए बीएओ विशाल गंगवार ने बताया कि कुल 600 किसानों में वितरण किया जाएगा। किसानों को में प्रति एकड़ 8 किलो बीज मूंग और मक्का का वितरण होगा। मालूम हो कि डुमरांव प्रखंड में रजिस्टर्ड किसानों की सख्या 23 हजार है, लेकिन बीज का वितरण मात्र छह सौ किसानों में वितरित होंगे ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस किसान को बीज नहीं मिलेगा उन्हें कितना निराशा होगी। बहरहाल जोभी हो, लेकिन बीज का वितरण शुरू होने से किसानों में काफी खुशी है।

केशव टाइम्स
डिजिटल संस्करण

बक्सर, 18 अप्रैल 2026
website:keshavtimes.com
e-mail:keshavtimes1@gmail.com

2027 जनगणना को लेकर प्रगणकों-पर्यवेक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण

■ प्रशिक्षण में अनुपस्थित फील्ड ट्रेनरों पर होगी कार्रवाई

केटी न्यूज/नवादा

प्रखंड में भारत जनगणना 2027 के परीक्षण के लिए पर्यवेक्षकों और प्रगणकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार से शुरू हो गया है। इस दौरान बिहार के जनगणना निदेशालय,पटना के निदेशक रंजीता के निर्देश पर प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 391गणना ब्लॉकों के लिए आयोजित किया जा रहा है,जिसमें 320 प्रगणक और 35 पर्यवेक्षक शामिल हैं। इन्हें 06 प्रशिक्षकों की सहायता से प्रशिक्षित किया जा रहा है। पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण रजौली अनुमंडल मुख्यालय स्थित इंटर विद्यालय परिसर में हो रहा है, जबकि प्रगणकों सभी तीन कमरों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का नेतृत्व बीडीओ संजीव झा ने करते हुए कहा कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण 16 से 24 तक अप्रैल तक चलेगा। जो प्रत्येक बैच में 44 प्रगणकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारत में यह जनगणना कार्य सत्र 2011 के बाद पुनः 2027 में

आयोजित होगी। जिसका 15 वर्षो तक विलंब होने का कारण कोविड-19 महामारी है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 2027 की जनगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूर्णरूप से चल रही हैं। इस पूर्व परीक्षण के तहत पूरे बिहार में नवादा जिले के रजौली प्रखंड,सारण के सोनपुर और सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड को चुना गया है। प्रशिक्षण का नेतृत्व बीडीओ संजीव झा ने बताया कि प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद,में से घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले जनगणना का कार्य पेन-पेपर मोड में होता था। लेकिन इस बार यह मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से किया जाएगा। इस डिजिटल प्रक्रिया में प्रगणक घरों के मैप के साथ डिजिटल मैपिंग का उपयोग कर जनगणना का कार्य संपादित करेंगे। साथ ही प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को जनगणना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है।

बिहार में फिर लगेगा जनता दरबार! अब सीएम सम्राट चौधरी सुनेंगे सीधे आपकी शिकायत

एजेंसी। पटना

बिहार की राजनीति में एक बार फिर जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की परंपरा लौटती नजर आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तर्ज पर जनता दरबार कार्यक्रम को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। इस पहल को सरकार और जनता के बीच दूरी कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। दरअसल, नीतीश कुमार के कार्यकाल में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम काफी लोकप्रिय रहा था। इस मंच के जरिए आम लोग सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखते थे और मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहते थे। इससे शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो पाता था और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता भी

बढ़ती थी। हालांकि कुछ निजी वजहों से इस कार्यक्रम को रोक दिया गया था। लेकिन अब सरकार बदली है तो इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। अब सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही उन्होंने जनता दरबार लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसी मॉडल को अपनाते हुए जनता दरबार लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। जानकारी के मुताबिक, उन्होंने इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसकी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। गुरुवार को उन्होंने सचिवालय पहुंचकर उस स्थान का निरीक्षण भी किया, जहां पहले जनता दरबार का आयोजन होता था। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से यह जानकारी ली कि कार्यक्रम को फिर से शुरू करने में किन-किन व्यवस्थाओं की जरूरत होगी और इसे किस तरह प्रभावी बनाया जा सकता है। सरकार का मानना है कि जनता दरबार के माध्यम से आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्हें सीधे मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, जिससे न सिर्फ उनकी समस्याओं का जल्दी समाधान होगा बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी जवाबदेही तय होगी। खास बात यह है कि इस दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे, ताकि शिकायतों का तुरंत निपटारा किया जा सके।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम जनता के बीच सरकार की पकड़ मजबूत करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही इससे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी जाएगा कि सरकार आम जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर है। हालांकि, जनता दरबार को सफल बनाने के लिए व्यवस्थाओं का मजबूत होना जरूरी है। भीड़ नियंत्रण, शिकायतों की सही तरीके से रिकॉर्डिंग और उनका समयबद्ध समाधान—ये सभी पहलू महत्वपूर्ण होंगे। अगर इन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया, तो यह पहल राज्य में सुशासन की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। फिलहाल यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में एक बार फिर जनता दरबार की शुरूआत होने जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी इस पहल को किस तरह से लागू करते हैं और यह जनता के लिए कितना प्रभावी साबित होता है।

सड़क दुर्घटना में अज्ञात ट्रक से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत,चालक फरार

■ आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम,पुलिस के पहल पर मानें परिजन

केटी न्यूज/रोहतास

शुक्रवार की अहले सुबह जब गांव की पगडंडियों पर सन्नाटा था और लोग अपने रोजमर्रा के कामों की शुरूआत भी नहीं कर पाए थे, तभी एनएच-120 पर एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया । काराकाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोथा मुख्य द्वार के पास सड़क किनारे पैदल जा रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कुचल दिया,जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई । मृतक की पहचान जयश्री गांव निवासी 55 वर्षीय स्वामीनाथ पासी उर्फ बउल पासी के रूप में हुई है,जो स्वर्गीय बलूंदर पासी उर्फ यमुना पासी के पुत्र थे । बताया जाता है कि स्वामीनाथ रोज की तरह सुबह करीब 5 बजे अपने घर से बगीचे की ओर निकले थे । लेकिन

उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा । जैसे ही वे मोथा द्वार के समीप पहुंचे,उसी दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें बेरहमी से रौंद डाला और चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया । टक्कर इतनी भयावह थी कि स्वामीनाथ पासी ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया ।घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर काराकाट, नासरीगंज, कछवां और राजपुर थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया। इस संदर्भ में काराकाट थानाध्यक्ष विवेक कुमार ने बताया कि अज्ञात वाहन और चालक की पहचान के लिए जांच तेज कर दी गई है। इस दर्दनाक हादसे ने एक परिवार पर दुःख का पहाड़ दिया है । स्वामीनाथ पासी अपने पीछे एक असहाय पत्नी को छोड़ गए हैं । उनकी कोई संतान नहीं थी । गांव में इस घटना के बाद मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और हर आंख नम है।

नरहट पुलिस ने बदलपुर गलारेत हत्याकांड का किया उद्भेदन, आरोपी

केटी न्यूज/नवादा

अनुमंडल के नरहट थाना क्षेत्र में करीब एक माह पूर्व बदलपुर बधार में गला काट हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मृतक का ही रिश्ते में भतीजा मुख्य आरोपी निकला,जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए रजौली के एसडीपीओ गुलशन कुमार और नवादा सदर के डीएसपी राजन कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बनायाबिगहा गांव निवासी स्व. महावीर प्रसाद के पुत्र अनुज प्रसाद की हत्या कर शव को बदलपुर बधार में फेंक दिया गया था। इस संबंध में मृतक की पत्नी अंशु देवी ने नरहट थाने में कांड संख्या 95/26 दर्ज कराते हुए संजय प्रसाद पिता अंक्षु महतो को नामजद आरोपी बनाया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संजय

प्रसाद को उसी दिन गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हालांकि,आगे की तकनीकी जांच के दौरान नए तथ्य सामने आए। इसके आधार पर पुलिस ने मृतक के भतीजे पप्पू कुमार पिता- सुनील प्रसाद को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार, आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया कुट्टी काटने वाला छुरा बरामद किया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी और मृतक के बीच रास्ते और पुराने विवाद को लेकर लंबे समय से तनाव था। हाल ही में गृह प्रवेश के दौरान हुए विवाद ने इस घटना का कारण बना। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। खून के छींटे कपड़ों पर न पड़ें, इसके लिए उसने घटना के समय केवल जांघिया पहन रखा था। थानाध्यक्ष गौतम कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

ज्ञान भारतम मिशन के पांडुलिपि संकलन पर विशेष अभियान का किया गया आयोजन

■ नवादा उप विकास आयुक्त नीलिमा साहु ने रजौली संगत का किया दौरा

केटी न्यूज/नवादा

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ह्यज्ञान भारतम मिशनह्ल के अंतर्गत नवादा जिले में उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन एवं उनके डिजिटलीकरण हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में उप विकास आयुक्त, नवादा नीलिमा साहु द्वारा रजौली संगत, रजौली का दौरा किया गया। इस दौरान पांडुलिपियों के सर्वेक्षण में लगभग 1400 पृष्ठों की 400 वर्ष पुरानी गुरुमुखी लिपि में हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब की महत्वपूर्ण

पांडुलिपि प्राप्त हुई, जिसे ज्ञान भारतम ऐप पर सफलतापूर्वक निबंधित किया गया।

उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य देश की समृद्ध बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़े अथवा पुराने कागजों पर लिखी पांडुलिपियों में प्राचीन ज्ञान, साहित्य, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान एवं स्थानीय इतिहास का महत्वपूर्ण भंडार निहित है, जो समय के साथ नष्ट होने के कगार पर हैं। इस मिशन के माध्यम से इन अमूल्य धरोहरों को आधुनिक तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाएगा।उन्होंने स्पष्ट किया कि पांडुलिपियों का स्वामित्व संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था के पास ही सुरक्षित रहेगा तथा जिला प्रशासन द्वारा केवल उनका वैज्ञानिक विधि से डिजिटलीकरण किया जाएगा, जिससे उन्हें राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी का हिस्सा बनाया जा सके।जिला प्रशासन द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें तथा अपने पास उपलब्ध अथवा जानकारी में आने वाली प्राचीन पांडुलिपियों की सूचना संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं।

महानायक वीर बांकुरा कुंवर सिंह का 23 अप्रैल को मानेगी भव्य विजयोत्सव

केटी न्यूज/आरा

शुक्रवार को महानायक वीर बांकुरा कुंवर सिंह के 23 अप्रैल को होने वाली विजयोत्सव आयोजन को लेकर एक सभागार लोगों ने की बैठक। जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता राजीव सिंह और संचालन ब्रजकिशोर सिंह व सुशील सिंह टाइगर ने संयुक्त रूप से किया। उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंह की वीरता साहस और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण यह सारा गुण आज के युवा में होना जरूरी है। कुंवर सिंह की सेना में सभी जाति धर्म के लोग थे और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सभी लोगों ने अपना जौहर दिखाकर अंग्रेजों को परास्त किया। ब्रजकिशोर सिंह बबलू ने कहा कि आजादी के महानायक वीर कुंवर सिंह ने अपने जीवन के अंतिम पायदान पर रहते हुए भी अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक

और अंग्रेजों को इस शाहाबाद और उत्तरप्रदेश के पूर्वांचल के धरती से उखाड़ कर फेंकने का कार्य किया। बैठक में शामिल लोग पूर्व वार्ड पार्षद भीमलाल, अंशु सिंह सिक्रिवाल, रोहित बजरंगी,अमीत पांडे आदि लोगों ने कहा कि इस विजयोत्सव के कार्यक्रम में अधिक से अधिक प्रबुद्ध जन शामिल होकर भव्य कार्यक्रम को सफल बनाएं।

एक नजर

बिक्रमगंज : बाल उपकारा में प्रशासन ने औचक निरीक्षण कर किया सघन जांच

बिक्रमगंज। थाना क्षेत्र बिक्रमगंज स्थित अनुमंडलीय करियवा बाल उपकारा में शुक्रवार की सुबह प्रशासन द्वारा सघन छापेमारी अभियान एसडीएम प्रभात कुमार के नेतृत्व में की गई। छापेमारी के दौरान एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह, उपकारा अधीक्षक मो. तारिक अनवर समेत उपकारा के अन्य अधिकारी और बिक्रमगंज अनुमंडल के विभिन्न थानों की पुलिस टीम मौजूद रही। जिसके तहत प्रशासन टीम ने उपकारा परिसर के विभिन्न वार्डो और बैरकों की गहन तलाशी किया। हालांकि इस दौरान कोई भी आपत्तिजनक या प्रतिबंधित सामान बरामद नहीं हुआ।अधिकारियों ने बताया कि जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से इस तरह की छापेमारी समय- समय पर की जाती है । प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आगे भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे,ताकि जेल परिसर में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे । इसकी जानकारी बिक्रमगंज उपकारा अधीक्षक मोहम्मद तारिक अनवर ने दी।

अग्नि सेवा सप्ताह पर आग से बचने के लिए लोगों को किया गया जागरूकता

बिक्रमगंज। नगर में अग्नि सेवा सप्ताह के अवसर पर अग्नि सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम न्यू मयूर होटल में अनुमंडलीय अग्निशमन अधिकारी अवध कुमार दास एवं जेईई के संयुक्त नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को आग लगने की स्थिति में सतर्कता बरतने,प्राथमिक उपाय अपनाने और समय रहते सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई । अधिकारियों ने बताया कि छोटी-छोटी सावधानियां अपनाकर बड़ी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अवसर पर अग्निशमन विभाग की टीम ने आग बुझाने के उपकरणों के सही उपयोग के बारे में भी जानकारी दी और लोगों को जागरूक रहने की अपील की । कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भागीदारी रही,जिन्होंने इस पहल की सराहना की । अधिकारियों ने कहा कि अग्नि सेवा सप्ताह का मुख्य उद्देश्य लोगों को आग से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षा के प्रति सजग बनाना है,ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में जान- माल की हानि को कम किया जा सके ।

विद्युत उपभोक्ता के समस्या निवारण के लिए विशेष शिविर का आयोजन

सासाराम। बिजली से जुड़ी समस्याओं से परेशान उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु 72 घंटे की समय-सीमा निर्धारित की गई है। जिससे उपभोक्ताओं कोआयोजन लंबी प्रतीक्षा से राहत मिल सके। इसी क्रम में विद्युत आपूर्ति प्रमंडल सासाराम के अंतर्गत सभी अवर प्रमंडल एवं प्रशाखा कार्यालयों में शुक्रवार को विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने भाग लेकर अपनी समस्याएं दर्ज कराईं। विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निष्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिससे उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिल सके। विद्युत कार्यपालक अभियंता, सासाराम ई. सुजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि अप्रैल माह में आगामी शिविर 20, 24 एवं 27 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक शिविर का समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है। ये शिविर सभी विद्युत कार्यालयों में, विशेषकर कनीय विद्युत अभियंता स्तर तक आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में बिजली बिल से संबंधित त्रुटियों का तत्काल सुधार किया जाएगा। साथ ही झुके हुए पोल, ढीले तार, कम वोल्टेज, खराब ट्रांसफार्मर जैसी तकनीकी समस्याओं पर मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि नए विद्युत कनेक्शन, नाम परिवर्तन एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी शिविर स्थल पर ही किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रक्रियाओं में भटकना न पड़े। इसके अतिरिक्त, कृषि कनेक्शन प्राप्त करने के इच्छुक किसानों के लिए भी यह शिविर उपयोगी सिद्ध हो रहा है। उन्हें आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों एवं अन्य औपचारिकताओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर कनेक्शन लेने के इच्छुक उपभोक्ताओं को भी मौके पर मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, जिससे योजना का लाभ उठाना सरल हो सके। यह पहल उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि उन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। विद्युत विभाग का उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं त्वरित बनाना है, जिससे उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ प्राप्त मिल सके।

अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा को लेकर लोगों को मॉक ड्रिल से किया जागरूक

रजौली। प्रखंड क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को अग्निशमन विभाग द्वारा विभिन्न प्रमुख स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान सम्राट होटल, हम तुम रेस्टोरेंट, बिजली विभाग कार्यालय एवं शहरी इलाके में आग से बचाव और नियंत्रण के उपायों का प्रदर्शन किया गया।मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया तथा आग बुझाने के आधुनिक तरीकों की जानकारी दी गई। टीम ने स्थानीय लोगों और कर्मचारियों को यह भी बताया कि आपात स्थिति में घबराने के बजाय सतर्कता और समझदारी से काम लेना कितना आवश्यक है। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान अग्निक सुरेंद्र कुमार शर्मा ने किया।

बिहार में स्व-गणना का शुभारंभ, डोर-स्टेप विजिट से पहले मोबाइल से करा सकते हैं अपनी गणना

एजेंसी। पटना

बिहार में जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दो मई प्रगणक घर-घर जाकर मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना करेंगे। लेकिन, इससे पहले यानी 17 अप्रैल से एक नई व्यवस्था की गई। इसके तहत बिहारवासी घर बैठे ही स्व-गणना कर सकते हैं। स्व-गणना करने की अंतिम तिथि एक मई रात 12 बजे तक है। 17 अप्रैल से एक मई तक बिहारवासी अपनी गणना मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री सचिवालय से माउस क्लिक कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यवासियों से जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना सुशासन की आधारशिला है, जो आगामी वर्षों में विकास योजनाओं, नीतियों और कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निमायेगी। जनगणना-2027 तकनीकी दृष्टि से एक ऐतिहासिक पहल है। इसमें पहली बार पूर्णतः डिजिटल डेटा संग्रहण तथा स्व-गणना की सुविधा 17 अप्रैल से एक मई उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जनगणना-2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य दो मई 2026 से 31 मई 2026 तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी नागरिकों से अपील करते हुये कहा कि वे इस राष्ट्रीय महत्व के अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लें। स्व-गणना के माध्यम से या प्रगणकों को सहयोग प्रदान कर एक सटीक, समावेशी और विश्वसनीय जनगणना संपन्न करने में अपना सहयोग दें। 'जनगणना-2027' बिहार एवं देश के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार करेगी।

पटना डीएम बोले- जानकारी गोपनीय रखी जाएगी

पटना ज़िलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जनगणना के दौरान प्राप्त सभी जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और इसका उपयोग केवल सरकारी योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण में किया जाएगा। जिला जनगणना कोषांग, पटना द्वारा इस कार्य की सतत निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जब भी प्रगणक उनके घर आएं, उन्हें सही एवं पूरी जानकारी दें, जिससे सटीक एवं विश्वसनीय आंकड़ों का संकलन संभव हो सके। जनगणना के आंकड़े देश के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, इसलिए इसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि पटना जिला में जनगणना कार्य के सुलभ एवं सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु 13-सदस्यीय जिला-स्तरीय जनगणना समन्वय समिति (डीएलसीसीसी) क्रियाशील है। साथ ही कार्यों के त्वरित गति से निष्पादन हेतु जिला जनगणना कोषांग भी सक्रिय है।

बिहार में हड़कंप : सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी गुजरात से आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी। पटना

बिहार की राजनीति और प्रशासनिक महकमे में उस वक्त हड़-कंप मच गया, जब राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिलने की खबर सामने आई। इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुंगेर पुलिस ने आरोपी को गुजरात के साणंद से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बांका जिले के मूल निवासी शेखर यादव के रूप में की गई है, जो वर्तमान में गुजरात में मजदूरी कर रहा था। जानकारी के अनुसार, आरोपी ने फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। जैसे ही यह सूचना पुलिस के संज्ञान में आई, इसे अत्यंत संवेदनशील मामला मानते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच शुरू कर दी गई। मुंगेर पुलिस ने इस पूरे मामले की गुप्त रूप से छानबीन की और तकनीकी अनुसंधान के जरिए आरोपी के लोकेशन का पता लगाया। एपुलिस सूत्रों के मुताबिक, धमकी देने के बाद आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था, जिससे उसकी गिरफ्तारी में कठिनाई आ रही थी। हालांकि, पुलिस की तकनीकी टीम और खुफिया इनपुट के आधार पर उसकी लोकेशन गुजरात के साणंद में ट्रेस की गई। इसके बाद मुंगेर पुलिस की एक विशेष टीम वहां पहुंची और स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जा रहा है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि धमकी देने के पीछे उसका मकसद क्या था और क्या इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति या संगठन भी शामिल है।इस घटना के सामने आने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय में भी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपी शेखर यादव आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आता है और रोजगार की तलाश में गुजरात गया था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने यह कदम क्यों उठाया। पुलिस उससे पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा कर पाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि तकनीकी संसाधनों और सतर्कता के जरिए पुलिस किसी भी आरोपी तक पहुंच सकती है, चाहे वह देश के किसी भी कोने में क्यों न छिपा हो। वहीं, मुख्यमंत्री को मिली धमकी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या जानकारी को तुरंत प्रशासन के साथ साझा करें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके और कानून-व्यवस्था बनी रहे।

मुंगेर के संग्रामपुर में दर्ज हुआ था कांड

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. इस घटना के बाद मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351(2), 351(3), 351(4), 352, 353, 224 के तहत मामला दर्ज किया गया था. सर्विलांस टीम ने तकनीकी स्त्रोतों और अन्य सोर्स के माध्यम से आरोपी का पता लगाया।

पूछताछ के दौरान स्वीकार किया अपराध

इसके बाद पता चलते ही सानंद (गुजरात) की पुलिस लगातार बिहार के पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहने लगी. फिर आरोपी के मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हो गई. पूछताछ के दौरान शेखर यादव ने अपराध स्वीकार किया. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गुजरात की पुलिस ने उसे बिहार पुलिस को सौंप दिया।

बांके के बेलहर का रहने वाला है शेखर

गिरफ्तार शेखर यादव के पिता का नाम कृष्णा यादव है. शेखर की उम्र 32 साल के आसपास बताई जा रही है. वह सानंद में थार ड्रायपोर्ट कंपनी में काम करता है. मूल रूप से बांका (बिहार) जिले के बेलहर के खेरौधा गांव का रहने वाला है. हालांकि उसने क्यों इस तरह का काम किया यह पूछताछ के बाद पता चलेगा।

दो दिनों में दूसरी बड़ी कार्रवाई : सेटिंग के भरोसे खेल कर रहा था रेवेन्यू अफसर, 40 हजार की घूस लेते निगरानी ने दबोचा

एजेंसी। पटना

बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई अब और तेज होती नजर आ रही है। ताजा मामला पूर्णिया से सामने आया है, जहां विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रेवन्यू अफसर और उसकी महिला सहयोगी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि यह कार्रवाई महज 30 घंटे के भीतर दूसरी रेड है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है। जानकारी के मुताबिक, पूर्णिया पूर्व अंचल में तैनात रेवन्यू अफसर लाल बाबू रजक पर आरोप है कि उन्होंने जमीन से जुड़े एक काम के बदले मोटी रकम की मांग की थी। गुलाबबाग वार्ड संख्या 35 निवासी ललिता देवी अपनी साढ़े तीन कट्ठा जमीन की स्टे रिपोर्ट जारी कराने के लिए कई दिनों से दफ्तर के चक्कर लगा रही थीं। आरोप है कि अफसर ने इस काम के बदले 50 हजार रुपये की मांग कर दी।खुद को बचाने के लिए लाल बाबू रजक ने एक चाल चली। उन्होंने पीड़िता से कहा कि पैसे सीधे उन्हें न देकर उनकी महिला सहयोगी रूबी कुंडी को दे दिए जाएं। उन्हें लगा कि इस तरह वे सीधे रिश्वत लेते हुए पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी यह चाल ज्यादा देर तक काम नहीं आई। उरिश्वत की मांग से परेशान होकर ललिता देवी ने विजिलेंस ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद डीएसपी अमरेंद्र प्रसाद विद्यार्थी के नेतृत्व में टीम गठित की गई और पूरे मामले की जांच की गई। योजना बनाकर टीम ने जाल बिछाया और सही समय का इंतजार किया। शुक्रवार को जैसे ही ललिता देवी ने 40 हजार रुपये की पहली किस्त रूबी कुंडी को सौंपी, पहले से मौजूद विजिलेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की पूरी रकम बरामद कर ली गई। पूछताछ में यह भी सामने आया कि कुल 50 हजार रुपये की डील हुई थी, जिसमें से 10 हजार रुपये बाद में देने थे।पूर्णिया में इतने कम समय में दूसरी बड़ी कार्रवाई ने सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मचा दिया है। यह साफ संकेत है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती बढ़ रही है और ऐसे मामलों में लिप्त लोगों पर लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारी चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, कानून की पकड़ से बच पाना आसान नहीं रह गया है।

दो राजस्व कर्मचारियों पर गिरी गाज, विभागीय कर्मियों को हड़ताल के लिए उकसाने का आरोप

एजेंसी। पटना

बिहार में पश्चिम चम्पारण जिले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए राजस्व कार्यों में व्यवधान डालने और कर्मचारियों को सामूहिक हड़ताल के लिए भड़काने के आरोप में दो राजस्व कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी तरनजोत सिंह द्वारा यह कार्रवाई की गई।मिली जानकारी के अनुसार, मझौलिया अंचल के राजस्व कर्मचारी ललन कुमार भारती और गौनाहा अंचल के राहुल रंजन पर आरोप है कि उन्होंने जिले के अन्य राजस्व कर्मियों को सामूहिक अवकाश लेने के लिए प्रेरित किया। इसके चलते 11 फरवरी 2026 से जिलेभर में राजस्व कर्मियों की हड़ताल शुरू हो गई, जिससे आम लोगों से जुड़े कई जरूरी कार्य प्रभावित हुए। हड़ताल के कारण जमाबंदी सुधार, आधार सीडिंग, सरकारी भूमि सत्यापन तथा लोक सेवाओं के अधिकार (फ्ळ्ढर) से जुड़े कार्य पूरी तरह ठप हो गए। इसके साथ ही जनगणना-2027 जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ा। प्रशासन द्वारा जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि दोनों कर्मियों ने मुख्य सचिव, बिहार के निदेशों की अनदेखी करते हुए साप्ताहिक बैठकों में सहयोग नहीं किया और वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 का उल्लंघन है। इन आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के तहत कार्रवाई करते हुए ललन कुमार भारती का निलंबन मुख्यालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, नरकटियागंज तथा राहुल रंजन का मुख्यालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, बगहा निर्धारित किया गया है।

एक नजर

बिहार में तेज रफ्तार का कहर: खड़ी ट्रक से टकराई बाइक, 16 वर्षीय किशोर की मौके पर मौत

मोतिहारी। बिहार में तेज रफ्तार एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। ताजा मामला मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी और मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह हादसा मोतिहारी-छपवा मुख्य मार्ग पर उस वक्त हुआ, जब तीन किशोर एक ही बाइक पर सवार होकर घूमने निकले थे। इसी दौरान तेज रफ्तार और असंतुलन के कारण बाइक सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 16 वर्षीय गोलू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसके साथ मौजूद 15 वर्षीय पप्पू कुमार और 12 वर्षीय मुन्ना गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बिना देर किए सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मोतिहारी सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद गोलू कुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं, घायल पप्पू कुमार और मुन्ना का इलाज जारी है। पप्पू की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतक गोलू कुमार की पहचान झखिया गांव निवासी कृष्णा सहनी के पुत्र के रूप में हुई है। वहीं घायल पप्पू कुमार अघन सहनी का बेटा और मुन्ना बनारसी सहनी का पुत्र बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है, वहीं पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

बिहार में दर्दनाक हादसा: मिट्टी धंसने से ननद-भौजाई की मौत, गांव में पसरा मातम

पूर्णिया । बिहार के पूर्णिया जिले में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों महिलाएं रिश्ते में ननद और भौजाई थीं। यह घटना बायसी थाना क्षेत्र के सुगवामहानंदपुर पंचायत अंतर्गत मसनतपुर गांव में हुई, जहां मिट्टी धंसने से दोनों महिलाएं दबकर जान गंवा बैठीं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार, दोनों महिलाएं शाम करीब पांच बजे जलकरिया नदी किनारे घर के लिए मिट्टी लाने गई थीं। मिट्टी काटने के दौरान नदी किनारे बना बड़ा टीला अचानक भरभराकर उन पर गिर पड़ा, जिससे दोनों महिलाएं मिट्टी के नीचे दब गईं। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान बारिक की पत्नी बीबी हसमती (35 वर्ष) और उसकी बहन सेमी खातून (19 वर्ष) के रूप में हुई है। सेमी खातून की शादी नहीं हुई थी, जबकि बीबी हसमती अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं। इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। थानाध्यक्ष शिवकुमार पासवान ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर डेंगराह ओपी पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

धार्मिक स्थल के पास बाजा बजाने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, 14 लोग गिरफ्तार

पटना। पश्चिमी चंपारण जिले के पुरुषोत्तमपुर थाना क्षेत्र के मझरिया गांव में धार्मिक स्थल के पास बारात में बज रहे बाजे को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया।जानकारी के अनुसार, मझरिया निवासी ललन कुशवाहा के यहां उनकी पुत्री की शादी थी, जिसमें बारात आई हुई थी। द्वारपूजा के दौरान डीजे बज रहा था। जब बारात धार्मिक स्थल के पास पहुंची, तो एक पक्ष के लोगों ने बाजा बंद करने को कहा। बताया जाता है कि डीजे संचालक ने बाजा बंद करने की सहमति भी जताई, लेकिन इसी बीच दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया।इसके बाद दोनों ओर से ईंट-पत्थर और लाठी-डंडे चलने लगे, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष के रहबर आदिल तथा दूसरे पक्ष के आकाश कुमार, चंद्रशेखर कुमार, राजन कुमार, कृष्ण कुमार और अंकित कुमार शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैनाटाड़ में कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही मैनाटाड़, पुरुषोत्तमपुर, इनरवा, भंगहा, बलथर, सिकटा, गोपालपुर और कंगली थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम तरनजोत सिंह, एसपी डॉ. शौर्य सुमन, एसडीएम अभिजीत कुमार गोविंदा और एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे।

गंगा में डूबकर बुझ गया घर का चिराग, गहरे पानी ने छीन ली जिंदगी, 14 वर्षीय छात्र की मौत

भागलपुर। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 14 वर्षीय किशोर की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान आर्यन कुमार के रूप में हुई है, जो गणेश मंडल के पुत्र थे और महमदपुर फुलवरिया गांव के निवासी थे।बताया जा रहा है कि आर्यन कुमार अपने घर से बरारी घाट नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान वह अनजाने में गहरे पानी में चला गया, जिससे वह डूबने लगा। आसपास मौजूद लोगों को जब तक घटना की जानकारी होती, तब तक काफी देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।आर्यन कुमार कक्षा 8 का छात्र था और पढ़ाई में भी अच्छा बताया जा रहा है। उसकी असमय मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने परिवार में दो भाइयों और तीन बहनों में शामिल था।

बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला! 13 विश्वविद्यालयों में नई ट्रांसफर नीति जल्द होगी लागू

एजेंसी। पटना

बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के अंतर-विश्वविद्यालय स्थानांतरण को लेकर लंबे समय से चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म होने वाली है। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सैयद अता हसनैन के निर्देश पर राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर स्तर तक के शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए नई नीति जल्द लागू की जाएगी। इस दिशा में पहल करते हुए राज्यपाल सचिवालय ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जो स्थानांतरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसा देगी। गठित कमेटी की अध्यक्षता प्रमेंद्र कुमार वाजपेयी करेंगे, जो जय प्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वहीं, कमेटी में उच्च शिक्षा निदेशक एन.के. अग्रवाल को सदस्य बनाया गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव अबू बकर को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष गिरिश कुमार चौधरी को आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कमेटी स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए ठोस सुझाव देगी। विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि नई नीति लागू होने के बाद विश्वविद्यालयों के बीच शिक्षकों के स्थानांतरण में आरक्षण रोस्टर का किसी भी स्थिति में उल्लंघन नहीं होगा। इससे सामाजिक न्याय और संवैधानिक प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा। बताया गया है कि बिहार लोक भवन के विश्वविद्यालय शाखा ने इस कमेटी को विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन कर एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट मिलने के बाद कुलाधिपति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा और उसी आधार पर नई स्थानांतरण नीति को लागू किया जाएगा।हालांकि, राज्य के सभी विश्वविद्यालय इस नीति के दायरे में नहीं आएंगे। पटना विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार कृषि विश्वविद्यालय को इस नीति से बाहर रखा गया है। दरअसल, इन विश्वविद्यालयों के अपने अलग अधिनियम हैं, जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए हैं, इसलिए उन पर इस नई नीति का सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नई नीति के लागू होने से विश्वविद्यालयों के बीच शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बनी कई विसंगतियों के दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक स्पष्ट नियमों के अभाव में कई बार शिक्षकों को स्थानांतरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहीं कुछ मामलों में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

पश्चिम चंपारण में तिरहुत मुख्य नहर पर बनेगा डबल लेन पुल, 10.71 करोड़ की मिली मंजूरी

एजेंसी। पटना

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में तिरहुत मुख्य नहर पर चमैनिया क्षेत्र में डबल लेन पुल का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर 10 करोड़ 71 लाख 90 हजार रुपये की लागत आएगी। जल संसाधन विभाग ने इसके लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। अधिकारियों के अनुसार, पुल का निर्माण कार्य अगले वर्ष मार्च से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह पुल गंडक बराज से निकलने वाली तिरहुत मुख्य नहर पर वाल्मीकिनगर से चंपापुर जाने वाले मार्ग पर चमैनिया क्षेत्र में बनाया जाएगा।इस पुल के निर्माण से लगभग 40 गांवों और टोलों के बीच आवागमन सुगम हो जाएगा। चमैनिया, सोनगढ़वा, चंपापुर, झरहरवा, सिवनाहा, गोनौली, पिपरा, धूमाटांड और देवतहा सहित एक दर्जन से अधिक पंचायतों के लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ये सभी क्षेत्र वाल्मीकिनगर व्याघ्र अभयारण्य के आसपास स्थित हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से इस पुल की मांग कर रहे थे, क्योंकि बरसात के मौसम में आवागमन में भारी परेशानी होती थी। पहले वन विभाग की आपत्ति के कारण परियोजना में देरी हो रही थी, लेकिन अब विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। सहमति मिलने के बाद जल संसाधन विभाग ने राशि जारी कर दी है, जिसकी निकासी बेतिया स्थित जिला कोषागार से की जाएगी। इस पुल के निर्माण से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को गति मिलने की उम्मीद है।